



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 2018/माघ 16, 1939

No. 51]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 2018/MAGHA 16, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2018

विषय - मलेशिया से टैक्सचर्ड टैम्पर्ड ग्लास चाहे कोटेड अथवा अनकोटेड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 6/45/2017-डीजीएडी.— मै. गुजरात बोरोसिल लिमिटेड (जिसे आगे याचिकाकर्ता या आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष मलेशिया (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से टैक्सचर्ड टफेन्ड (टैम्पर्ड) ग्लास जिसमें न्यूनतम 90.5 प्रतिशत ट्रांसमिशन हो मोटाई 4.2 मिमी. से अधिक न हो (0.2 मिमी. की सहनशीलता सहित) और जहां कम से कम एक किनारा 1500 मिमी. से अधिक हो, चाहे कोटेड अथवा अनकोटेड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

विचाराधीन उत्पाद

1. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद टैक्सचर्ड टफेन्ड (टैम्पर्ड) ग्लास जिसमें न्यूनतम 90.5 प्रतिशत ट्रांसमिशन हो मोटाई 4.2 मिमी. से अधिक न हो (0.2 मिमी. की सहनशीलता सहित) और जहां कम से कम एक किनारा 1500 मिमी. से अधिक हो, चाहे कोटेड अथवा अनकोटेड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) है। संबद्ध वस्तु में अपेक्षित न्यूनतम अपेक्षित ट्रांसमिशन स्तर को लौह अवयव को कम,

विशेष रूप से 200 पीपीएमसे कम, रखकर प्राप्त किया जा सकता है। जब इसे रिफ्लेक्शन रोधी कोटिंग तरल से कोट किया जाता है तो ट्रांसमिशन का स्तर लगभग 2-3 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। ग्लास चाहें कोटेड या अनकोटेड को एक टैम्परिंग भट्टी में टैम्पर्ड/टफेन्ड किया जाता है क्योंकि सौर अनुप्रयोगों के लिए यह अनिवार्य है। इस उत्पाद को बाजार की शब्दावली में विभिन्न नामों जैसे सोलर ग्लास, लो आयरन सोलर ग्लास, उच्च ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टैम्पर्ड लो आयरन पैटर्नड सोलर ग्लास आदि से भी जाना जाता है।

2. संबद्ध वस्तु का प्रयोग सौर फोटोवोल्टिक पैनलों और सौर तापीय अनुप्रयोगों में किया जाता है। 3.2 मिमी. और 4 मिमी. की मोटाई के ग्लास का उपयोग आम तौर पर वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार सौर फोटोवोल्टिक पैनलों और सौर तापीय अनुप्रयोगों में किया जाता है। संबद्ध वस्तु को अध्याय शीर्ष 70071900 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तु को विभिन्न अन्य टैरिफ शीर्षों जैसे 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900 आदि के अधीन भी वर्गीकृत किया जा रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और उत्पाद को विवरण सभी परिस्थितियों में लागू होगा।

3. विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

‘टैक्सचर्ड टफेन्ड (टैम्पर्ड) ग्लास जिसमें न्यूनतम 90.5 प्रतिशत ट्रांसमिशन हो मोटाई 4.2 मिमी. से अधिक न हो (0.2 मिमी. की सहनशीलता सहित) और जहां कम से कम एक किनारा 1500 मिमी. से अधिक हो, चाहे कोटेड अथवा अनकोटेड’

समान वस्तु

4. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु समान वस्तु हैं। संबद्ध देश से निर्यातित और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टैक्सचर्ड टफेन्ड (टैम्पर्ड) ग्लास और संबद्ध देशों से आयातित टैक्सचर्ड टफेन्ड (टैम्पर्ड) ग्लास भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें ‘समान वस्तु’ माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के ‘समान वस्तु’ माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

5. यह आवेदन मै. गुजरात बोरोसिल लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में दायर किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार वे भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता ने प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा या उसके किसी संबद्ध पक्ष द्वारा संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता भारत में विचाराधीन उत्पाद के समूचे उत्पादन (100 प्रतिशत) का उत्पादन करता है इसलिए याचिकाकर्ता नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग की योग्यता को पूरा करता है और घरेलू उद्योग है।

शामिल देश

6. वर्तमान जांच मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य

7. आवेदक ने सामान्य मूल्य का दावा भारत में उत्पादन लागत के आधार पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके किया है। प्राधिकारी ने अपने संगत मानकों/पद्धति के अनुसार उसका आकलन किया है और उसे डब्लूटीए आकड़ों के अनुसार पीओआई के दौरान मलेशिया से तीसरे देश की औसत निर्यात कीमत के साथ उसे सहसंबंधित किया है।

निर्यात कीमत

8. आवेदक द्वारा डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा प्रकाशित आकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। कमीशन, समुद्री भाड़े, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री बीमा, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए कीमत संबंधी समायोजनों का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

9. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के संबंध में पर्याप्त पाटन मार्जिन को दर्शाता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुएं पाटित की जा रही हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंध

10. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से वास्तविक क्षति हुई है। विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और संबद्ध आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है। आयातों ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू कीमतों में हास/न्यूनीकरण किया है। घरेलू उद्योग पर आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में मापदंडों जैसे लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ के संबंध में विकृति आई है। घरेलू उद्योग भारी वित्तीय घाटा, नकद घाटा और निवेशों पर नकारात्मक आय उठा रहा है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

11. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियमावली के पैरा 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

जाँच अवधि (पीओआई)

12. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ प्रस्तावित जाँच अवधि 1 अक्टूबर, 2016 से 30 सितम्बर, 2017 (12 महीनों) की है। तथापि, प्राधिकारी ने पीयूसी के अद्यतन आयातों को प्राप्त करने के लिए 1 अक्टूबर, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 (15 महीने) पर जाँच अवधि के रूप में विचार किया गया है। क्षति जाँच अवधि में विगत तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 2014 से मार्च 2015, अप्रैल 2015 से मार्च 2016, अप्रैल 2016 से मार्च 2017 और जाँच अवधि के आकड़े शामिल होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग,
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल ,

**5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली - 110001**

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

समय-सीमा

15. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना मूल प्रतियों तथा साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता का दावा करने के मामले में दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

18. गोपनीय या अगोपनीय अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां दो (2) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

19. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

20. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

23. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2018

Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Textured Tempered Glass whether Coated or Uncoated from Malaysia

No. 6/45/2017-DGAD.— M/s Gujarat Borosil Limited (hereinafter also referred to as the Petitioner or Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of "Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated" (hereinafter also referred to as the subject goods or PUC) from Malaysia (hereinafter also referred to as the subject country).

Product under consideration

1. The product under consideration in the present application is "Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated" (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "Product under Consideration"). The minimum level of transmission required in the subject good can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid. The glass whether coated or uncoated is tempered / toughened in a tempering furnace, as it is essential for solar applications. The product in the market parlance is also known by various names such as Solar Glass, Low Iron Solar Glass, High Transmission Photovoltaic Glass, Tempered Low Iron Patterned Solar Glass etc.

2. The subject good is used as a component in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications. The glass of thickness 3.2 mm and 4 mm is generally used in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications as per the current trend. The subject goods are classified under chapter heading 70071900. However, it has been claimed by the petitioner that the subject goods are also being imported under various other tariff headings like 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900 etc. It is clarified that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

3. The Product under Consideration is defined as follows:

“Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated”.

Like Article

4. The petitioner has submitted that subject goods produced by the petitioner company and the subject goods imported from the subject country are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from subject country and that produced by the petitioner. Textured Toughened (Tempered) Glass produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

5. The Application has been filed by M/s Gujarat Borosil Limited., as domestic industry of the product under consideration. According to the Petitioner, they are the sole producers of the subject goods in India. The petitioner has certified that there are no imports of the product under consideration by the petitioner or any of its related party from the subject country. Since the petitioner account for entire (100%) production of the product under consideration in India, the petitioner satisfies the standing and constitutes Domestic Industry within the meaning of the Rules.

Country involved

6. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from Malaysia.

Normal Value

7. The applicant has claimed the normal value based on cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses and reasonable profit. The Authority has assessed the same as per its consistent norms / methodology and also correlates the same with 3rd country average export price from Malaysia during POI as per WTA’s data.

Export Price

8. The applicant has claimed the export price on the basis of data published by DGCI&S, Kolkata. Price adjustments have been claimed on account of commission, ocean freight, port expenses, inland freight, marine insurance, credit cost and bank charges.

Dumping Margin

9. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which show significant dumping margin in respect of the subject goods from the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Injury and Causal Link

10. The applicant has claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports. The demand for the product under consideration has increased over the injury period and subject imports have increased in absolute terms. The imports are undercutting the domestic prices. The imports have suppressed/depressed the domestic prices. With regard to consequent impact of the imports on the domestic industry, it is noted that performance of the domestic industry has deteriorated in respect of parameters such as profits; return on capital employed and cash profits. The domestic industry is suffering financial losses, cash losses and negative return on investments. There is sufficient prima facie evidence of injury to the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.
11. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Period of Investigation (POI)

12. The period of investigation proposed for the purpose of present investigation is from 1st October 2016 to 30th September 2017 (12 months). However, the Authority has considered POI as 1st October 2016 to 31st December 2017 (15 months) to capture the latest imports of PUC. The injury investigation period will cover the data of previous three years, i.e. April 2014 to March-2015, April 2015 to March 2016, April 2016 to March-2017 and POI.

Submission of Information

13. The exporters in the subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Department of Commerce, Jeevan Tara
Building, 4th Floor
5, Parliament Street
New Delhi -110001

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

15. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

17. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof.
18. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.
19. The confidential version shall contain all information, which is by nature confidential and/or other information, which the supplier of such information claims, as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
23. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

24. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the information or evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

25. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority